REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 6 | MARCH - 2019

''वैश्वीकरण के दौर में भारत–ईरान सम्बंधों में चाबहार बन्दरगाह का महत्व''

इन्दु
शोधछात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय),लखनऊ.

सारांश:

वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्षेत्रीय वस्तुओं को विश्व बाजार में रूपांतरित करना। जैसे–पूरा विश्व एक समाज या परिवार हो तथा सभी मिल कर एक साथ कार्य करते हैं। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि आयामों का संयोजन होता है। वैश्वीकरण का अर्थ अक्सर आर्थिक या व्यापार से ही जोड़ा जाता है इसमें प्रौद्योगिकी, तकनीकी हस्तांतरण आदि भी शामिल है। साधारण शब्दों में कहें तो वैश्वीकरण का अर्थ है–आर्थिक या व्यापारिक सीमाओं को हटा देना। इसकी वजह से आज विश्व का कोई भी शहर अछूता या अन्जान नहीं रह गया है, विकास की लहर हर–तरफ देखी जा सकती है। भारत–ईरान का संबंध देखा जाए तो यह हड़प्पा कालिन से रहा है, सीमाओं से परे दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार, सांस्कृतिक आदान–प्रदान सदियों से कर रहे हैं लेकिन 1991 के बाद दोनो दशों में काफी बदलाव देखे जा सकतें हैं। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सदियों पुराने मित्र ईरान से राजनीतिक एवं आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संधि किया है। इसी संधि में एक व्यापारिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह परियोजना भी है इस परियोजना से भारत मध्य एशिया एवं यूरोप तक अपनी पहुंच आसानी से बना सकता है।

मुख्यशब्द- वैश्वीकरण,चाबहार,प्रौद्योगिकी,सांस्कृतिक,ऊर्जा संसाधन

प्रस्तावना:

वैश्वीकरण का तात्पर्य है, विस्तृत या विश्वव्यापी दृष्टिकोण को अपनाना। अर्थात् वैश्वीकरण एक ऐसी प्रकिया है जिसमें विश्व समाज को एक सूत्र में पिरोया जाये, कियाशील व प्रगतिशील बनाया जा सके साथ ही, विश्व की उन्नति के लिये आर्थिक, तकनीकी व सास्कृतिक अदान–प्रदान हो।

अर्थशास्त्री जगदीश भगवती का मत है कि ''वैश्वीकरण को अधिकांशतः आर्थिक सार्वभौमिकता के रूप में जाना जाता है, यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को व्यापार, विदेशी विनियम, पूंजी निवेश, प्रवजन और तकनीकी के विस्तार के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से एकीकृत करता है।[1]''

वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक निवेश में सहायता प्राप्त होता है।[2]

---

[1]Bhagwati, j. (2004).In difense of globalization; with a new afterword.oxford university press.
[2]What Is Globalization?, Globalizations A project of Suny Levin Institute Retrieved form https://www.globalization101.org/what-is-globalization/ .

LBP PUBLICATION

वैश्वीकरण के सन्दर्भ में सारे विश्व को एक बाजार की दृष्टि से देखा जाता है। वैश्वीकरण में विदेशी बाजार और घरेलू बाजार विभेद लगभग खत्म हो जाता है, जिससे व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। वैश्वीकरण केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि यह तकनीकी, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आ गया है। जिसके परिणाम स्वरूप सूचना संचार क्रान्ति, तकनीकी हस्तांतरण, शिक्षा आदि पर बहुत प्रभाव पड़ा है, इससे पूरा विश्व एक कुटुम्ब बन गया है। तकनीकी क्रान्ति ने समाज के भौतिक आधार को तीव्रता से विकसित किया है। विश्व में एक–दूसरे देश पर निर्भरता बढ़ गई है।

वैश्वीकरण का प्रभावः

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्वीकरण के दौर में इसको प्रभावी ढंग से लागू करने या सफल बनाने के लिए उद्योगों एवं व्यापार की बाढ़ सी आ गई। इन उद्योगों से निकला माल बाजार में खपाने के लिए एवं उद्योगों का लाभ दिलाने के लिए बहुत से संगठन बनाए गये जिससे व्यापार एवं बाजार का दायरा बढ़ गया। तकनीकी के विकास से वैश्वीकरण में उद्योग–धंधों और व्यापार में अतिशय सफल परिणाम आने लगे। मुक्त व्यापार से प्रतिबंध हटा लिया गया, यह संभव हो सका क्योंकि शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT), विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन (WTO) आदि ने पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।[3] इससे कंपनियां अपना उत्पाद किसी भी देश के बाजार में पहुंच बनाने में सफल हो गई।

अगर वैश्वीकरण के लाभ देखा जाए तो यह तकनीकी विकास के साथ–साथ भगौलिक रूप से दूरस्थ स्थानों तक सूचना टेलीफोन संचार, परिवहन आदि की पहुंच हो गई है इससे वैश्वीकरण की महत्ता भी बढ़ गई है। वैश्वीकरण का दूसरा पहलू यह है कि इस बौद्धिक संपदाओं का उपभोग, जलवायु परिवर्तन, सीमा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, कल–कारखानों का अन्धा–धुंध निर्माण से वनों का दोहन, मृदा क्षरण आदि से विश्व पर्यावरण पर खतरा मंडराने लगा है।[4]

यह वैश्वीकरण के प्रभाव ही है कि विश्व को समान लाभ मिलने के बजाय प्राकृतिक संसाधन और स्त्रोतों का असमान बंटवारा भी हो रहा है इस संसाधन में प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन प्रमुख घटक है। यही वजह है कि ऊर्जा विश्व के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, जिसका प्रत्येक देश भण्डारण करने के लिए प्रयासरत है।वैश्वीकरण पूंजीवाद विकास के मौजूदा चरण का नाम इसमें औद्योगिक पूंजी भी विश्व के किसी भी कोने में जाकर निवेश कर सकती है। वैश्वीकरण को पहली बार लैटिन अमेरिकी देश चिली में इन नीतियों को लागू किया गया था।

दूसरे महायुद्ध के बाद विकसित पूंजीवादी देशों ने तेज गति से आर्थिक वृद्धि दर्ज की परन्तु दो महायुद्धों की वजह से खनिज संसाधनों की खपत बहुत हो गयी थी, विश्व के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ लग गयी थी, जिससे वर्तमान समय में भारत सहित पूरी दुनिया को ऊर्जा के भीषण संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है।

1990–91 से 'भूमण्डलीकरण' नाम से जन्में शब्द ने मुक्त बाजारवाद में दमकते सिक्के की तरह अपना स्थान बना लिया था। परन्तु उस समय भी 'भूमण्डलीकरण' का वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं था। बहुत ही सीमित अर्थ में 'भूमण्डलीकरण' का अर्थ था – मुक्त बाजारवाद और अमेरिकी विश्व दृष्टि। सम्भवतः भूमण्डलीकरण को विश्व पटल पर मजबूत और आकर्षक बनाने में अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था।[5] अमेरिका एक तरह से वैश्वीकरण (भूमण्डलीकरण) को गॉड–फादर बन गया था उस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री 'महाठीर मोहम्मद' ने भूमण्डलीकरण की कड़ी आलोचना की थी। भूमण्डलीकरण की वजह से अमीर देश और अमीर, गरीब देश और भी गरीब होते जा रहे थे। वैश्वीकरण की अमेरिकी राजनीति का विरोध करने वालों ने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि 11 सितम्बर, 2001 में जो विनाश हुआ वह वैश्वीकरण का ही नतीजा था, जिसने

[3]Narlikar, A. (2004). *International trade and developing countries: Bargaining coalitions in GATT and WTO*. Routledge.
[4]Bunker, S. G., & Ciccantell, P. S. (2005). *Globalization and the Race for Resources*.JHU Press.

[5]Higgott, R. A. (2003). American unilateralism, foreign economic policy and the'securitisation'of globalisation.

अमीर और गरीब देशों की खाइयों को और बढ़ा दिया है क्योंकि उन लोगों का मानना था कि भूमण्डलीकरण ने असुरक्षा एवं भय का बीज बोया है।

वैश्वीकरण की वजह से आज पूरा विश्व तो साथ आ गया है, परन्तु राजनीतिक रूप से सब दूर ही हैं केवल अपने राष्ट्रीय हित की वजह से ही सब साथ रहने का अभिनय कर रहें हैं। वर्तमान में पूंजीवादी व्यवस्था हावी है, इन सबके बावजूद आज भारत–ईरान को सम्बन्धों की बात की जाए तो यह सबसे प्राचीन एवं भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाला एक महत्वपूर्ण मित्र एवं विश्वसनीय देश है। वर्तमान में तेल, गैस और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन दुनिया में ऊर्जा की कुल मांग के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से से पूर्ति करते है। भारत में ऊर्जा का उत्पादन बहुत कम और खपत बहुत ज्यादा है। इसलिए भारत को दूसरे देशों पर ऊर्जा की निर्भरता के साथ–साथ अपने प्राकृतिक संसाधन (पारम्परिक और गैर पारम्परिक) का संरक्षण एवं दोहन पर विशेष ध्यान देना होगा वरना आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं छोड़ पाएंगे।[6]

शीत युद्धोंपरान्त भूमण्डलीकरण के दौर में सुरक्षा की अवधारणा में अनेक बातें सम्मिलित हुई हैं, जिसका सम्बन्ध ऊर्जा से है। जहाँ पर पश्चिम एशिया प्राकृतिक तेल एवं गैस से सम्पन्न है, वहीं पर दक्षिण एशिया में जनसंख्या की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी है। जब हम इन बातों को संज्ञान में लेते हैं, तो भारत और ईरान के सम्बन्धों की चर्चा स्वाभाविक रूप से उठती है। भारत और ईरान का सम्बन्ध कोई नई घटना नहीं है, वरन् इसकी जड़े इतिहास में निहित रही हैं। यही कारण है, कि ईरान और भारत में किसी की भी सरकार रही हो, दोनों देशों के बीच एक आपसी समझ हमेशा बना रहा है। यह सम्बन्ध बहुत ही स्वाभाविक समझदारी से बंधा है और एक दूसरे का पूरक भी है। ऊर्जा की कमी से आज पूरा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा है। यह संकट प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में अत्यधिक ऊर्जा की खपत की वजह से और गहरा हो गया है जिसका खामियाजा आज पूरा विश्व भुगत रहा है।

21 वीं सदी में भारत में विश्व की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, इतनी बड़ी जनसंख्या की ऊर्जा की मांग को पूरा करना भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत पश्चिमी एवं खाड़ी के देशों ईरान, सउदी अरब, अमेरिका, इराक आदि देशों से कच्चा तेल, गैस, कोयला आदि का आयात करता है।आज देश को तीव्र विकास की आवश्यकता है, परन्तु भारत की ऊर्जा आवश्यकता की निर्भरता बाह्य देशों से प्राप्त ऊर्जा पर निर्भर है। अतः भारत की प्रमुख आवश्यकता है, कि ऊर्जा निर्भरता वाले देशों के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ बनाये। भारत का ईरान के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से घनिष्ठ संबंध रहा है। ईरान के पास ऊर्जा का अपार भंडार है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। ईरान की आवश्यकताओं को हम और हमारी आवश्यकताओं को ईरान पूरा करने में सक्षम है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारत–ईरान सम्बन्धः

भारत–ईरान के बीच मित्रवत, सह संवाद स्वतंत्रता पूर्व से रहे हैं। दोनों देशों के बीच भाषा, संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों में समान सहभागिता रही है। ऊर्जा सुरक्षा की बात आये और भारत–ईरान सम्बन्धों की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान तथा अन्य खाड़ी देशों से भारत की हड़प्पा संस्कृति मेलुहा (हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र) से व्यापारिक सम्बन्ध था, जिसमें मेलुहा से लकड़ी, ताँबा एवं कई प्रकार के बीज और सोने का व्यापार होता था।

स्वतंत्र भारत और ईरान ने 15 मार्च, 1950 को राजनयिक संबंध स्थापित किए। तेहरान में भारतीय दूतावास के अलावा भारत का ईरान में फिलहाल दो कांसुलावास–बंदर अब्बास तथा जहेदान में हैं। शाह ने फरवरी/मार्च, 1956 में भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने सितंबर, 1959 में ईरान का दौरा किया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अप्रैल, 1974 में और प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने जून, 1970 में ईरान का दौरा किया। इसके बाद, शाह ने फरवरी, 1978 में भारत का दौरा किया।[7]

---

[6]Najam, A., Runnalls, D., & Halle, M. (2016). Environment and Globalization: Five Propositions (2010). *The Globalization and Environment Reader*, 94.

[7]https://www.indianembassy-tehran.ir/

1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तथा शाह का शासन खत्म हो गया। उसके बाद आपसी संबंधों की एक नई शुरुआत हुई। 2012 में ईरान के ऊर्जा मंत्री माजिद नामजू "ऊर्जा पहुंच पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार" में हिस्सा लेने के लिए भारत का दौरा किया था।[8]

जुलाई, 2015 में ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में दोनों देशों के आपसी हितों के अनेक मसलों पर बातचीत हुई थी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच समय–समय पर आपसी बातचीत व विभिन्न मुद्दों पर दानों देशों के बीच आवागमन रहा है। भारत ईरान के सांस्कृतिक संबंध भी बहुत मजबूत हैं। इन्हीं संबंधों में मिठास लाने के लिए ईरान में 7 से 12 जून, 2012 तक भारत–ईरान सांस्तिक महोत्सव का आयोजन हुआ था।

भारत–ईरान का सम्बन्ध सदियों पुराना है, परन्तु इसकी कूटनीतिक शुरूआत 1950 से मानी जाती है, क्योंकि भारत ने अपनी बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए तेल और गैस आयात हेतु समझौता किया। इसका मुख्य कारण था, कि ईरान के पास दुनिया का 15 प्रतिशत प्राकृतिक गैस संरक्षित है तथा विश्व में इसका दूसरा स्थान है।ईरान भारत में तेल का दूसरा सबसे बढ़ा निर्यातक था, लेकिन अब यह पांचवें स्थान पर पहुंच गया है।[9]

ईरान एक मुस्लिम देश है तथा यहाँ प्राकृतिक संसाधनो का विशाल भण्डार है। यही विशेषता ईरान को अन्य देशों से अलग पहचान देती है। ईरान में तेल की प्रमुख कम्पनी 1920 में आस्तित्व में आयी तथा 1970 के मध्य तक यह विश्व की चौथी पेट्रोलियम उत्पादन कम्पनी थी और 1989 तक चौथे नम्बर पर बनी रही। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रान्ति के बाद भी प्राकृतिक संसाधनों में कमी नहीं आयी, जो वर्तमान तक जारी है। भारत ईरान से तेल आयात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है जोकि 2017 में 11.2 प्रतिशत था और वहीं ईराक 18.6 प्रतिशत के साथ विश्व का प्रथम देश बना तथा दूसरा स्थान साऊदी अरब (17.5 प्रतिशत)प्राप्त किया।[10]आज प्राकृतिक संसाधनों की वजह से ईरान का आर्थिक विकास बहुत ऊपर उठ चुका है। जिसमें तेल और गैस का मुख्य निर्यात ही ईरान की विकसित अर्थव्यवस्था एवं उसकी आमदनी का माध्यम बन गया है।

भारत ईरान संबधों में उतार–चढ़ावः

सर्वविदित है कि भारत–ईरान का संबंध सदियों से मित्रवत चला आ रहा है परंतु भारत–अमेरिका जैसे–जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे–वैसे ईरान भारत में खाई बढ़ती जा रही है या यह कहें कि संबंध रसातल में चले जा रहे हैं। शीत युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच मित्रता ठीक चल रही थी क्योंकि भारत की जरूरत ऊर्जा थी और यह ऊर्जा ईरान से मिल रही थी, ईरान को भारत से खाद्य, मशीनरी आदि प्राप्त हो रहा था जिससे दोनों देश खुश थे परंतु अमेरिकी दबाव में आकर भारत ने 2005 में परमाणु परीक्षण रोक के लिए ईरान के खिलाफ वोट डाल दिया। यहीं से रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई हलांकि ईरान ने स्पष्ट किया कि वह भारत को मित्र मानता है आगे भी इस रिश्ते में कोई बदलाव नहीं होगा। एक तरफ भारत की ऊर्जा की जरूरत और दूसरी तरफ अमेरिका से असैन्य परमाणु करार की वजह से न चाहते हुए भी अमेरिका के साथ भारत को एक विश्वसनीय एवं परममित्र से दूर ले जा रहा है। अमेरिका भी यही चाहता है कि भारत, ईरान–अमेरिका में से किसी एक को चुनें।

भारत–ईरान को चुनता है तो उससे मिलने वाली सहायता बंद कर दी जाएगी और अमेरिका को चुनता है तो उसे एक मित्र राष्ट्र खोना पड़ेगा। भारत को जल्द से जल्द बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया है और पूरे विश्व को आगाह किया है कि 4 नवंबर, 2018 तक सभी देश ईरान से तेल आयात कम कर दें और 6 माह के अंदर तेल आयात शून्य कर दें नहीं तो इसके बुरे परिणाम

---

[8] iwoksZDrA

[9] Oil & Gas Journal, Worldwide look at reserves and production, (December 2017).

[10] Daniel Workman, "Crude Oil Imports by Country," World's Top Exports, May 11, 2018, http://www.worldstopexports.com/crude-oil-imports-by-country/.

भुगतने पड़ेंगे। 2+2 वार्ता में भी अमेरिका ने भारत को ईरान से आयात कम करने को कहा, बातचीत के बाद अमेरिका ने भारत को समय दिया है।[11]

भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ने ईरान से तेल आयात बंद करने को कहा है परंतु आयात बंद करने के बाद जो संकट आएगा उससे कैसे निपटा जा सकता हैं नहीं बताया है।

इस प्रतिबंध की वजह से भारत को भी ईरान से तेल आयात कम करना पड़ रहा है। तेल आयात के भुगतान को लेकर भारत–ईरान में वार्ता चल रही है जिससे समय पर भुगतान किया जा सके। इन समस्याओं से उबरने के लिए भारत–ईरान में बातचीत जारी है जिससे संबंध सुचारू रूप से चलता रहे।

भारत ईरान सम्बन्धों में नया आयामः चाबहार बन्दरगाहः

ईरान में विकसित हो रहा चाबहार बंदरगाह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है परंतु जब से अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया है तब से इस परियोजना भी संशय के बादल छाने लगे थे परंतु अमेरिका ने इस बंदरगाह को प्रतिबंध से अलग रखा है साथ ही इसे अफगानिस्तान से जोड़ने वाली रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए छूट दिया है। इस बंदरगाह के पूरा होने से भारत, ईरान के रास्ते अफगानिस्तान तक पहुंच बना सकता है। चाबहार बंदरगाह 1970 के दशक में अस्तित्व में आया था। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ईरान के दक्षिणी तट पर है तथा ऊर्जा संसाधन से संपन्न है। भारत के पश्चिमी तट से यहां सरलता से पहुंच सकते हैं। चाबहार बंदरगाह में कम निवेश को लेकर ईरान–भारत की आलोचना कर चुका है। ईरान का कहना है, कि यदि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत–ईरान से तेल आयात में कमी या कटौती करता है, तो उसे ईरान से मिलने वाले विशेष लाभ को खत्म किया जा सकता है।

भारतीय उद्योगों को अपना सामान ईरान भेजने के लिए एक मार्ग की आवश्यकता थी जो ईरान के बाजार में पहुंच बना सके, यह मार्ग चाबहार बंदरगाह ने पूरा कर दिया। इसे भारत न केवल ईरान बल्कि मध्य एशिया में अपनी पहुंच आसानी से बना सकता है, इस बंदरगाह के कारण भारत को पाकिस्तान के अंदर से होकर अफगानिस्तान या ईरान नहीं जाना पड़ेगा, इससे समय में भी बचत होगा। चाबहार बंदरगाह भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना है परन्तु इससे भारत के साथ–साथ ईरान एवं अफगानिस्तान को भी बहुत फायदा होगा। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बंदरगाहों से व्यापार करना पड़ता था परन्तु चाबहार बंदरगाह के विकसित होने से इसको ज्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि अफगानिस्तान के पास अपना कोई बंदरगाह नहीं है, इसलिए भी यह बंदरगाह अफगानिस्तान के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। चाबहार बन्दरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बंदरगाह के विकसित होने से ईरान को भी एक स्वतंत्र बंदरगाह मिल गया है, क्योंकि 'बन्दार अब्बास' पर बड़े देशों द्वारा चौकसी की जाती है इसलिए भी चाबहार बंदरगाह ईरान के लिए महत्वपूर्ण है।

2002–03 के लगभग चाबहार बंदरगाह की नींव रखी गई थी[12] उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति खातमी और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर हस्ताक्षर किया परंतु कुछ कारणों से यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई लेकिन 2015 में इसे फिर से शुरू करने का अभियान चला। इस परियोजना में यह अनुबंध है कि भारत और ईरान की कंपनियों के बीच जो व्यापार होगा वह इसी बंदरगाह के माध्य से ही होगा अर्थात व्यापार के लिए इसी बंदरगाह का उपयोग किया जाएगा। चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान से सड़क मार्ग से जोड़ेगा इससे भारत की पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। भविष्य में भारत अन्य देशों से भी जुड़ सके ऐसा इस परियोजना में विकास किया जा रहा है।

कुछ समय से भारत ईरान संबंधों में कटुता आई है, परन्तु इस परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है आशा है कि अमेरिकी प्रतिबन्ध का इस परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा भविष्य में भारत अपनी पहुंच

---

[11] All you need to know: 2+2 Dialogue between India, US to ramp up strategic relations (2 September 2018) The New Indian Express. Retrieved from http://www.newindianexpress.com/thesundaystandard/2018/sep/02/all-you-need-to-know-22-dialogue-between-india-us-to-ramp-up-strategic-relations-1866282.html

[12] Chabahar port begins commercial operations: Why Iran's port is important for India (January 8, 2019). India Today. Retrieved form https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/india-takes-over-operations-chabahar-port-iran-importance-1426057-2019-01-08

मध्य एशिया के साथ–साथ खाड़ी देशों और यूरोप तक व्यापारिक एवं सामरिक संबंध स्थापित कर पायेगा। साथ ही अपने व्यापार सहयोगी देशों से जुड़ने में आसान हो जाएगा।फरवरी 2019 से इस बंदरगाह से अफगानिस्तान में निर्यात शुरू भी कर दिया है यह एक सुखद भविष्य का द्वार ही कहा जा सकता है। वर्तमान में आस्ट्रेलिया, ईरान आदि से यूरेनियम, ऊर्जा सन्धि करके भारत ने ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है। भारत और ईरान संयुक्त निवेश के लिए बैंकिंग क्षेत्र की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सहमत हो गये है। यह इलैक्ट्रोनिक्स ऑटो मोबाईल, सूचना प्रौद्योगिकी और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भी हो सकता है। भारत–ईरान और रूस के मध्य एक नई रेल लिंक स्थापित करने के लिए अप्रैल 2008 में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। चाबाहर मुक्त व्यापार क्षेत्र में भारत लगभग 10 लाख यू0एस0 डॉलर का निवेश र चुका है।

आई0पी0आई0 परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भारत ईरान के साथ आर्थिक, कूटनीतिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ावा दे रहा है। वर्तमान में भारत की विदेश नीति में काफी बदलाव आया है, इसके बावजूद भी परियोजना की प्रगति रूकी हुई है। यह परियोजना आगे नहीं बढ़ी तो भारत को पश्चिमी देशों से ही गैस एवं तेल का आयात करना पड़ेगा। भारत का ईरान के साथ सम्बन्ध बहुत ही सौहार्दपूर्ण है तथा दोनों देश इसे बनाये रखने में विश्वास रखते हैं, एवं आपसी बातचीत द्वारा सम्बन्धों को आगे ले जाना चाहते हैं।

निष्कर्ष :

वैश्वीकरण के दौर में भारत विश्व स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, इसके साथ ही यह विश्व राजनीति और व्यापार की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहा है। तकनीकी हस्तांतरण से सामान्य जीवन के साथ–साथ तकनीकी विकास होने से दुनिया छोटी लगने लगी है। सर्वविदित है कि भारत–ईरान मित्रवत संबंध शताब्दियों सदी पुराना है, दोनों देश मित्रता की मिसाल है परंतु कुछ समय से अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ ज्यादा होने से भारत की सदियों पुरानी दोस्ती में दरार आने लगी। देखा जाए तो भारत–ईरान का संबंध ऊर्जा, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से ज्यादा जुड़ा हुआ है इसमें ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है परंतु अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगा देने से भारत का भी अपना तेल आयात को कम करना पड़ रहा है इससे भारत का पूरा ध्यान चाबहार परियोजना पर है क्योंकि अमेरिका ने इसको प्रतिबंध से अलग रखा है। चाबहार बंदरगाह में निवेश में कमी को लेकर ईरान भारत से नाराजगी जता चुका है, चाबहार भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है इसका काम लगभग पूर्ण हो चुका है। भारत का ईरान के साथ संबंध खराब होना उसी समय से शुरू हो गया था जब से भारत ने ईरान के खिलाफ परमाणु परीक्षण के विरुद्ध वोट डाला था। इसके बावजूद भी संबंध सही था परंतु भारत–ईरान संबंधों में अमेरिका ने जब से सेंध मारी है तब से भारत–ईरान का संबंध रसातल में चला गया है। भारत को अपने मित्र राष्ट्र को छोड़कर अमेरिका से संबंधों के बारे में गहन विचार–विमर्श की जरूरत है, वरना देश एक विश्वसनीय मित्र से दूर हो जायेगा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान से हम रुपया में भुगतान करके तेल आयात करते हैं, अमेरिका आदि देशों से हमें डॉलर में भुगतान करना होगा। इसलिए हमें ईरान की शर्त पर अमेरिका से दोस्ती के बारे में सोचना होगा और ऐसा कोई रास्ता निकालना होगा जिससे दोनों देशों के साथ संबंधों में संतुलन बना रहे।

सन्दर्भ सूचीः

पांडे, सुरेश कुमार (2016), *वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव,* बिजनेस एडिटोरियल, हिंदी व्यापार।

श्रीवास्तव, असीम और कोठारी आशीष (2017), *भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव पर्यावरण समाज और अर्थव्यवस्थाए,* https://hindiindiawaterpoltal.org

भारत ईरान संबंध, भारत के दूतावासः तेहरान की बेवसाइट, अगस्त, 2015, https://wwwindianembassy-tehran.ir

अफगानिस्तान ने भारत के लिए खोला नया रास्ता (2019), www.navbharattimes.com/

सिंह, उमाशंकर (2018), *ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए अमेरिका ने प्रतिबंधों से भारत को छूट दी,* https://khabar.ndtv.com

ईरान ने साधा भारत पर निशाना कहा तेल का आयात कम करने पर विशेष लाभ खत्म, (2018), https://khabar.ndtv.com

पालीवाल, कृष्णदत्त (2008), *उत्तर आधुनिकतावाद और दलित साहित्य,* प्रकाशनः वाणी प्रकाशन, दिल्ली।

काबरा, कमन नयन (2013), *नव उदारवादी नीतियां नाकामी और दुराग्रह,* वैकल्पिक आर्थिक समीक्षा, प्रकाशनः युवा संवाद प्रकाश, नई दिल्ली।

खेतान, प्रभा (2014), *भूमण्डलीकरण ब्रांड संस्कृति और राष्ट्र,* प्रकाशनः सामायिक प्रकाशन, नई दिल्ली।

Alam, Anwer(July 2011) *India and Iran An Assessment of Contemporary Relations,* Publisher: New Century Publication.

Boylis, John, Smith, Steve and Owens Patricia (2011), *The Globalization of World Politic.*

Daboshi, Hamid (1993), "Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran", New York: University Press.

Fazali, Nematollah (2006), "Politics of Culture in Iran Anthropology: Politics and Society in the twentieth Century", New York: Routledge Publication.

Jeannie, Marion and Bille, Publisher: Oxford University Press

Mohammadi, Ali (2003), "Iran Encountering Globalization: Problems and Prospects", New York: Routledge Curzon.

Mohmood, Fazal and Azmi, Refiullah, *Foreign Policy of India and West Asia: Change and Continuty*

Pasha, Adnan Khalil (31 July, 2000), *India Iran and the GCC States: Political Strategy and Foreign Policy,* Publisher: Manas Publication

Qamas, G. A. (30 Sep. 2011), *The early cultural relations of India and Iran,* Publisher: Dev Books, Edition 01.

Roy, Meena Singh (2009), "International and Regional Security Dynamics: India and Iranian Perspectives", New Delhi: IDSA.

Shah, Anup (06 Dec. 2011), "US, India and Iran", *Social, Political, Economic and Environmental Issues.*

Stiglitz, Joseph (2006), *Making Globalization Work,* publicer: W.W. Norton & Company.

Wasley, Michael (2007), "Energy Security in Asia", New York: Routledge Publication.

Yadav, R. S. (2013), "Bharat Ki Videsh Niti", New Delhi: Darling Kinderslay (India) Pvt. Ltd.

पत्र–पत्रिका

1. वर्ल्ड फोकस
2. चाणक्य
3. भारत

समाचार पत्र

1. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया
2. नव भारत टाइम्स
3. द हिन्दू

इन्दु
शोधछात्रा , राजनीति विज्ञान विभाग , बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय),लखनऊ.